कोटद्वार, गुरूवार
29 अगस्त 2024
वर्षः 46
अंकः 122 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

गंगोत्री हाईवे पर रातभर ठप रही आवाजाही

उत्तरकाशी। मंगलवार रात करीब 11 बजे भारी बारिश के कारण गुफियारा क्षेत्र में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिट्टी पत्थर गिरने से हाईवे पर यातायात ठप हो गया था। हालांकि पुलिस ने रात में ही उत्तरकाशी से तेखला की ओर ट्रैफिक को जीरो जोन घोषित कर दिया था। यातायात को मनेरा बाईपास की ओर से डायवर्ट किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस टीमें लगातार पेट्रोलिंग करती रही। बुधवार को सुबह लगभग आठ बजे इस जगह पर स्थिति सामान्य होने पर यातायात को फिर से चालू कर दिया गया। इस तरह हाईवे पर कुल नौ घंटे आवाजाही ठप रही। हालांकि दोपहर तक जेसीबी मशीन गुफियारा में हाईवे से मिट्टी पत्थर को हटाने में जुटी रही। हाईवे पर बहते पानी और कीचड़ होने से यातायात काफी प्रभावित रहा। मुसाफिरों को उत्तरकाशी से लेकर जगह–जगह जलभराव और कीचड़ के कारण आवागमन में भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। फिलहाल, गंगोत्री मार्ग सहित उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मार्ग पर यातायात सुचारू है। उधर तेखला–महिडाण्डा सड़क किमी 6 पर क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। इस मार्ग के बंद होने से आईटीबीपी सेना महिडांडा का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। बुधवार को मार्ग बाधित रहने से सेना तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पाया।

ग्रामीणों द्वारा सप्ताह भर पहले श्रमदान से बनाई पुलिया नदी में बही

उत्तरकाशी। जिले में मंगलवार देर रात को हुई भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। यहां रंवाई घाटी के पुरोला क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने तल्डा के ग्रामीणों को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। ग्रामीणों की ओर से एक सप्ताह पूर्व बनाई गई लकड़ी की पुलिया मंगलवार रात को कमल नदी में समा गई। जिससे ग्रामीणों के समक्ष फिर से आवागमन का संकट पैदा हो गया है। पुरोला में मंगलवार क्षेत्र में देर रात को हुई मूसलाधार बारिश और कमल नदी में उफान के चलते ग्रामीणों की श्रमदान कर बनाई गई लकड़ी की अस्थायी पुलिया तेज बहाव में बह गई। जिससे एक बार फिर से 35 परिवारों के तलडा गांव के लोगों को आवाजाही की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों ने विधायक और जिला प्रशासन से उक्त स्थान पर लोगों की परेशानी को देखते नई आरसीसी पुलिया बनाने की गुहार लगाई है। स्थानीय सुशील चमोली, बलवीर सिंह, अनिल रावत, रितिक चमोली, विपिन, हरवीर राणा आदि ने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही मामले का संज्ञान नहीं लिया तो वह तहसील में कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे।

स्कूल गई नाबालिग लापता, अपहरण की आशंका

विकासनगर। स्कूल गई एक नबालिग लापता हो गई। परिजनों ने एक व्यक्ति पर नाबालिग के अपरहण की आशंका जताई है। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष सेलाकुई शैंकी कुमार ने बताया कि क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि मंगलवार को सुबह साढ़े सात बजे वह अपनी नाबालिग बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। दोपहर को जब लेने गई तो उसे उसकी बेटी स्कूल में नहीं मिली। इस संबंध में जब अध्यापकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह स्कूल नहीं आई। महिला ने बताया कि राशिद नाम का युवक एक दिन उनके घर आया था। इसके बाद उन्होंने युवक को धमकाया था, लेकिन बदनामी के डर से कानूनी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने युवक पर उनकी बेटी का बहला–फुसलाकर कर अपहरण करने की आशंका जताई है।

कर्णप्रयाग–ग्वालदम मार्ग में बोल्डरों से खतरा

चमोली। कर्णप्रयाग–ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनला स्लाइडिंग जोन पर पहाड़ी में मलबे में दबे बड़े–बड़े बोल्डर दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। वाहन चालक जान जोखिम में डालकर अपना सफर पूरा कर रहे हैं। सड़क पर भारी मलबा तथा बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण कई राहगीर गिर कर चोटिल हो रहे हैं। चंदन सिंह गुसाई और मनीष सेजवाल ने बताया कि सड़क की पहाड़ी पर अटके बड़े–बड़े बोल्डर हल्की बारिश होने पर दुर्घटना को न्योता दे सकते है।

बदलते भारत की तस्वीर जनता तक पहुंचाएं : धामी

● मुख्यमंत्री धामी ने किया भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में प्रतिभाग

देहरादून। एक सितंबर से शुरू होने वाले भाजपा के सदस्यता अभियान–2024 को लेकर बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी में हुई भाजपा संयुक्त मोर्चा की कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के साथ उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं, अब भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। सदस्यता अभियान सिर्फ पार्टी के लिए सदस्य बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सामज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच बनानी है और जनता तक बदलते हुए भारत की तस्वीर पहुंचानी है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़े जो भाजपा की विचारधारा पर विश्वास करते हों और राष्ट्र और समाज के निर्माण में योगदान दे सके। कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाना है। सभी वर्गों के लोगों को पार्टी से जोड़ना है। कहा कि नए लोगों के पार्टी से जुड़ने से हमारी ताकत और बढ़ेगी। इस अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास भी होगा, उनकी जनता तक पहुंच बढ़ेगी, इसलिए कर्तव्यनिष्ठता के साथ इस काम को करें। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में देश में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उत्तराखंड में भी पीएम के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का भी यह एक सुनहरा अवसर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सदस्यता अभियन को सफल बनाने के लिए एकजुटता से काम करने को कहा। इस मौके पर संगठन मंत्री अजय कुमार, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक कुलदीप कुमार, महामंत्री राजेंद्र बिष्ट, खिलेंद्र चौधरी और आदित्य कोठारी, भाजयमुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, राष्ट्रीय मंत्री एससी मोर्चा स्वराज विद्वान, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर रावत, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह पुंडीर, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, रतन सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

सड़क दुर्घटना में रुद्रप्रयाग के दो युवकों की मौत

विकासनगर। देहरादून–विकासनगर मार्ग पर बाइक सवार दो युवक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने 108 एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों युवक रुद्रप्रयाग के ग्राम कांडा के निवासी थे। दोनों लांघा रोड स्थित अलग–अलग कंपनियों में काम करते थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं।

थानाध्यक्ष सहसपुर मुकेश त्यागी ने बताया कि रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि देहरादून– विकासनगर मार्ग पर जस्सोवाला के निकट बाइक सवार दो युवक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर तत्काल थाना सहसपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां दो युवक सड़क पर घायल अवस्था में पड़े थे। पुलिस ने दोनों को 108 एंबुलेंस की मदद से विकासनगर उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक लांघा रोड स्थित अलग–अलग कंपनियों में काम करते थे। दोनों लांघा रोड पर ही कमरा लेकर रहते थे।

बंगाल बंद के दौरान बीजेपी नेता पर फायरिंग

रेलवे ट्रैक पर उतरे समर्थक, राज्य में दिखा रहा बंद का असर

कोलकाता , ट्रेनी महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद कोलकाता में रोष प्रदर्शन किए जा रहे है। इसी बीच बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने भी बंगाल बंद का ऐलान किया है। भाजपा के बंगाल बंद का प्रदेश में असर भी देखने को मिल रहा है। भाजपा समर्थकों ने हावड़ा व सियालदह मंडल सहित कई जगहों पर ट्रेन सेवा को बाधित कर दिया। विभिन्न स्टेशनों पर बंद समर्थक ट्रेन के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दूरगामी ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। बंद के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के भिड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं।

इसी बीच भाटपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर फायरिंग हुई है। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि भाटपाड़ा में भाजपा नेता प्रियंगु पांडे की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग में कार पर सवार एक बीजेपी समर्थक घायल हुआ है। बीजेपी समर्थक का नाम रवि सिंह बताया जा रहा है। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा, प्रियंगु पांडे हमारे पार्टी नेता हैं। आज उनकी कार पर हमला किया गया और गोलीबारी की गई। ड्राइवर को गोली लगी है। यह एसीपी की मौजूदगी में किया गया। प्रियंगु पांडे को मारने की योजना बनाई गई थी। टीएमसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए वे इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं, उनमें से एक गंभीर हैं।

जिन्ना की तरह ही समाज को बांटने का कार्य कर रही है कांग्रेस-सपा-सीएम योगी

अलीगढ़ , उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, इसलिए वह अंतिम समय में घुट–घुट कर मरे थे। समाज को बांटकर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को अलीगढ़ में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला को संबोधित किया। साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब विपक्ष के लोग समाज को तोडने का काम कर रहे हैं। साल 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ समूचा विपक्ष समाज में जाति का विष घोल कर अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है। जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कारनामे किए आज उन्हें प्रदेश में कानून–व्यवस्था का राज पसंद नहीं आ रहा है। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कहते थे कि लडके हैं और लडकों से गलती हो जाती है। यही लोग हैं जो बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता की घटना पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों को जब भी सत्ता प्राप्त हुई तो सामाजिक ताने–बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टिकरण करते थे और समाज को विकास की धारा से विमुख करने का कार्य करते थे।

सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे राष्ट्र नायकों का अपमान किया है। भाजपा ही है, जो इन महापुरुषों को सम्मान देने का कार्य कर रही है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है।

कंगना रनौत के खिलाफ आप पार्टी उतरी सड़कों पर

भिवानी ,हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत खुद के बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। उनके बयान को लेकर मनोरंजन से लेकर सियासी दुनिया तक कई बार विवाद हो चुका है। कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसानों पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई।बता दें कि आज भिवानी में आम आदमी पार्टी ने विवादित बयान को लेकर स्थानीय घण्टाघर चौक पर प्रदर्शन किया तथा उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उनके सांसद पद से इस्तीफे की मांग की है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सांसद द्वारा किसानों के प्रति दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हैं तथा मांग करते हैं कि जो भी मंत्री, विधायक, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां किसान, खिलाड़ीयो पर करते हैं ,उनका भाजपा बड़ी लीडरशिप को इस्तीफा लेना चाहिए।

महिलाओं और युवाओं को सम्मान देने में सर्वोपरि रही प्रधानमंत्री जनधन योजना : पीएम मोदी

नई दिल्ली ,प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के 10 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ पूरे होने पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ह्यएक्सह्न पर एक पोस्ट शेयर किया और लाभार्थियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए। सभी लाभार्थियों को बधाई और इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को बधाई। जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए 53.13 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। इनमें 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। सीतारमण ने कहा, हमारा लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान तीन करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोलना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। मार्च 2015 में प्रति खाते में औसत बैंक बैलेंस 1,065 रुपये था, जो अब बढक़र 4,352 रुपये हो गया है। करीब 80 फीसदी खाते सक्रिय हैं। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में 66.6 फीसदी जनधन खाते खोले गए हैं, इनमें से 29.56 करोड़ (55.6 फीसद) महिला खाताधारकों के हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही है। इसके साथ साथ ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी फायदा सीधे लाभार्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है।

हनोल के लिए शीघ्र शुरू होगी गंगा यमुना एक्सप्रेस ट्रेन: महाराज

● पर्यटन मंत्री महाराज ने जागड़ा पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक ली ● हिमाचल के परिवहन मंत्री से हनोल तक बस चलवाने का किया अनुरोध

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जौनसार भाबर के प्रमुख तीर्थ स्थल हनोल स्थित ह्नमहासू देवता मंदिर में राजकीय मेला ह्नजागड़ा पर्वह्न की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को गढ़ी कैंट स्थित आई.एच.एम. परिसर में जौनसार भाबर के प्रमुख तीर्थ स्थल हनोल स्थित महासू देवता मंदिरष् में 06–07 सितम्बर, 2024 को होने वाले राजकीय मेला जागड़ा पर्व की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आरटीओ, उप जिलाधिकारी, चकराता, अध्यक्ष, हनोल मंदिर समिति, लोक निर्माण विभाग, महाप्रबंधक, जल संस्थान तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हनोल मंदिर राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। महासू देवता मंदिर में पूजन दर्शन के लिए उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं इसलिए उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। परिवहन एवं संड़कों की कनेक्टिविटी के साथ साथ पार्किंग और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। साफ–सफाई का ध्यान रखने के अलावा शौचालयों का उचित प्रबंध होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, पानी, जनरेटर की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और श्रृद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में दो समय के भण्डारे की व्यवस्था होनी चाहिए।

बैठक के दौरान पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जागड़ा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उचित पुलिस बल तैनात किया जाए और पूर्व की भांति जौनसार भाबर तथा उत्तरकाशी क्षेत्र में स्कूलों में जागड़ा पर्व के दौरान सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।

सरकार गिराने के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ली चुटकी

देहरादून। विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी ली है। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश ने कहा कि कहीं न कहीं कुछ आग लगी है, इसलिए धुआं निकल रहा है। विधानसभा में किसी ने बात उठाई और पीठ ने चुपचाप सुन लिया। सरकार गिराने की साजिश, एक गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए बयान दिया है कि खुफिया एजेंसीज इस पर काम करेंगी। मतलब, स्पष्ट है, कहीं न कहीं कुछ चल रहा है, जिसका आभास मुख्यमंत्री को भी है। इस पर हरीश ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि जब भाजपा, सरकार गिराने के एक्सपर्ट्स को अपनी पार्टी में ले गई है तो वह कुछ न कुछ तो अपना हुनर दिखाएंगे ही। जेब कतरे को कभी यदि कोई जेब कतरने को नहीं मिलती तो वह अपने ही घर के लोगों की जेब कतर देता है। उनका इशारा किसकी ओर है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है।

वनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

नैनीताल। हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उन्हें वैधानिक जमानत (डिफॉल्ट बेल) दे दी है। बीते शनिवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पुलिस द्वारा 90 दिन बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र पेश नहीं किया और आरोप पत्र पेश करने के लिए और समय दिया गया था। हिंसा के आरोपी मुजम्मिल और 49 अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट में डिफॉल्ट बेल का प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि पुलिस ने उनके खिलाफ न तो 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल किया है और न ही रिमांड बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट कारण बताया है। निचली अदालत ने उनकी रिमांड बढ़ाकर उनकी डिफॉल्ट बेल खारिज कर दी। वहीं, सरकारी पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण हैं। साथ ही अदालत के पास रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। नियमानुसार ही आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई है। सुनवाई पर आरोपियों की ओर से कहा गया कि जो समय बढ़ाया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। चाहे उनके ऊपर कितने भी बड़े आरोप क्यों न हों, पुलिस बिना किसी कारण उन्हें जेल में नहीं रख सकती है। कहा कि अभी तक आरोप पत्र पेश नहीं हुआ है, ऐसे में उनका अधिकार है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

10 दिन के बाद रांची पहुंचे चंपई सोरेन ने कहा

झारखंड के हित में लिया भाजपा में शामिल होने का फैसला

रांची ,झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने बहुत सोच–समझकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। यह झारखंड के हित में लिया गया बिल्कुल सही फैसला है। दिल्ली से रांची लौटने के बाद सोरेन ने यहां पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। सोरेन 10 दिन के बाद रांची आए हैं। यहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ज्यादातर लोग उनके निर्वाचन क्षेत्र से आए थे, जिनका कहना था कि चंपई सोरेन जो भी निर्णय लेंगे, वे उनके साथ हैं। खबर है कि कि चंपई सोरेन आज ही मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने 26 अगस्त की रात असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसमें उनके भाजपा में शामिल होने पर सहमति बनी थी। इसके बाद 27 अगस्त को उनकी केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात हुई। इसके पहले चंपई सोरेन ने 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा था कि झामुमो में उनका अपमान हुआ। जिस तरह से उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया गया, उससे वह आहत हैं।

चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आयोजित होने वाले एक वृहत कार्यक्रम में भाजपा में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन भी पार्टी की सदस्यता लेंगे। चर्चा है कि झामुमो के कुछ अन्य बड़े चेहरे भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

सत्संग सुनने आए लोगों पर गिरी दीवार, 60 से अधिक लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर

पटना ,बिहार के पटना जिले के पुनपुन में बुधवार को एक धार्मिक आयोजन के दौरान पास की एक दीवार गिर जाने से कम से कम 5 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, श्रीपालपुर में बुधवार को नीरज सिंह के आवास के पास एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में करीब 140–150 लोग एकत्र हुए थे। भजन–कीर्तन, पूजा–अर्चना का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक पास की दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आने से कम से कम 5 दर्जन लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में अफरा–तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस घटना में कई लोग मलबे में भी दब गए थे। दानापुर की डिप्टी एसपी पल्लवी कुमारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दीवार के नीचे दबे लोगों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालने में जुट गई।

बस अब बहुत हो गया, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली , कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप के मामले में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वह भयभीत हैं, कोई सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ ऐसी अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने निर्भया कांड का भी जिक्र किया। मुर्मू ने कहा– बस अब बहुत हो गया। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे, तो दूसरी जगहों पर अपराधी सक्रिय थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि समाज को ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ आत्म–विश्लेषण करने की आवश्यकता है। लोगों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे। बहुत बार एक निंदनीय मानसिकता महिलाओं को एक कमजोर, कम सक्षम, कम बुद्धिमान इंसान के रूप में देखती है।

आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जो समाज अपने इतिहास का सामना करने से डरते हैं, वे सामूहिक भूलने का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। यह घटना हमें स्तब्ध और भयभीत करती है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं कर सकता।

संपादकीय

भंवर में फंसी ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शायद यह उम्मीद नहीं रही होगी कि चिकित्सक से रेप का प्रकरण आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी इस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद पूरे देश में चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर पूरा स्वास्थ्य तंत्र एकजुट हो गया तो वहीं पश्चिम बंगाल का यह कांड राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। ममता बनर्जी अपने बिखरे हुए पश्चिम बंगाल को समेटने का प्रयास कर रही है लेकिन परिस्थितियां है कि संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। बात यहां तक पहुंच गई है कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता की संभावनाओं के बाद खुलेआम धमकी देने पर उतर आई है। एक जनसभा में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता की महिला डॉक्टर की हत्या की घटना की आड़ में बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बंगाल को जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली सहित अन्य राज्य भी जलेंगे। आपकी कुर्सी हिल जाएगी"। पहले से ही जल रहे पश्चिम बंगाल में इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है और ममता के इस बयान को सीधे तौर पर दूसरे राज्यों में हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने तो इस बयान के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दुष्कर्म–हत्याकांड के करीब तीन सप्ताह बाद भी तनाव जारी है। ममता फिलहाल इस विवाद से उबरती हुई नजर नहीं आ रही है और संभावनाएं तो इस बात की जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल के हालातो को देखते हुए यहां राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। ममता बनर्जी को कूटनीतिक तरीके से अब इस मुद्दे को संभालना होगा अन्यथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अभी यह लगता नहीं की बंगाल के हालात जल्दी सुधरने वाले हैं। ममता बनर्जी जितने आग उगलने वाले विवादास्पद बयान देगी उतना ही पश्चिम बंगाल में अशांति फैलेगी और ममता के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा लामबंद होगा। वर्तमान परिस्थितियों में ममता बनर्जी की छटपटाहट साफ नजर आ रही है और इस नाजुक समय में यदि वह अपना विवेक होती है तो इसकी एक बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है, वहीं यदि वह इस सबसे आसानी से पार हो जाती है तो उनकी भूमिका राजनीतिक मंच पर एक मजबूत नेता के रूप में उभरेगी।

'सेकुलर सिविल कोड' के रूप में नयी अवधारणा

प्रभु चावला

हलचल से भरी राजनीति में हैमलेट के शब्दों– 'शब्द, शब्द, शब्द' के अनेक अर्थ हैं। शब्द क्षणों और विचारधाराओं को परिभाषित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में एक ऐसा शब्द प्रयुक्त कर सभी को चौंका दिया, जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता। उन्होंने 'सेकुलर सिविल कोड' के रूप में नयी अवधारणा दी। उन्होंने घोषित किया कि देश को धार्मिक आधार पर बांटने और भेदभाव पैदा करने वाले कानूनों के लिए आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है, इसलिए देश के लिए समय आ गया है कि वह एक सेकुलर सिविल कोड की मांग करे।

उन्होंने रेखांकित किया कि मौजूदा नागरिक संहिता सांप्रदायिक सिविल कोड है और विभाजनकारी है। अच्छे विवाद खड़े करना मोदी को पसंद है। यदि उनके नये नैरेटिव के पीछे उनका इरादा यह था कि इस पर बहस हो या इसे समर्थन मिले, तो यह उन्हें हासिल हुआ है। इससे भ्रम भी फैला है और संघ परिवार भी इस नये नागरिक संहिता के बारे में समझ बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले जनसंघ और फिर भाजपा द्वारा हर चुनाव में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया जाता रहा है। उसके घोषणापत्र में नागरिक संहिता और अनुच्छेद 370 हटाने के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता था।

विपक्ष, जिसकी विचारधारा के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता है, को लगता है कि इस शब्द से प्रधानमंत्री का औचक लगाव राजनीतिक विमर्श को निर्देशित करने की उनकी घटती ताकत का परिचायक है।

संघ के बड़े नेता अपनी आंतरिक बैठकों में इस पर जल्दी कुछ करने का निवेदन कर रहे हैं। भाजपा के लोग इस सेकुलर कवायद को मोदी का मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। इसीलिए इस बात में दम दिखता है कि अपनी कई पहलों पर पैर पीछे खींचने वाली सरकार इस मुद्दे पर कुछ ठोस करना चाहती है। प्रारूप पर काम चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था क्योंकि भाजपा को प्रचंड बहुमत की आशा थी। सरकार को अपने सहयोगी दलों के विरोध के बाद वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। मोदी सरकार को लैटरल एंट्री के मामले में भी पीछे हटना पड़ा है। लैटरल एंट्री के तहत 45 अफसरों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस पर खूब विरोध हुआ। उसमें दिव्यांग लोगों के लिए एक श्रेणी थी। हाल के दिनों में इस श्रेणी में फर्जीवाड़े से भर्ती के अनेक मामले सामने आये हैं। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सरकार में लाने का यह विचार नीति आयोग का था, जिसने बिना आरक्षण के बड़ी संख्या में युवा पेशेवरों को भर्ती किया है। साल 2018 से 63 अधिकारियों को बिना आरक्षण के सीधे नियुक्त किया गया है। भाजपा को पूर्ण बहुमत था और विपक्ष मरणासन्न था, तो मोदी को इस मामले में कोई चुनौती नहीं मिली थी। लेकिन 2024 के जनादेश ने सत्ता के भगवा रंग को फीका कर दिया है। सहयोगी दल उन मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, जिनका उनके लिए वैचारिक महत्व है।

दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च नेता द्वारा धर्मनिरपेक्षता को महत्व देने से उनके इरादे के बारे में सवाल उठ रहे हैं।

चुनाव अभियान के दौरान भाजपा के नेता समान नागरिक संहिता को देश को एकताबद्ध करने के एकमात्र उपाय के रूप में देख रहे थे। अल्पसंख्यकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को मुद्दा बनाकर भाजपा लगातार नागरिक संहिता को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए हथियार बनाती रही है। अब मोदी ने बिना विवरण बताये सेकुलर बनाम कम्युनल कोड की बहस शुरू कर दी है। उन्होंने या किसी मंत्री या भाजपा नेता ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस कोड में क्या–क्या होगा। ऐसे में संघ परिवार के सदस्यों में भ्रम की स्थिति है। जहां गूढ़ मंशा होगी, वहां कयास लगाया जाना स्वाभाविक है। मोदी के विरोधियों का मानना है कि ऐसी बातें तेलुगू देशम और जद(यू) जैसे सहयोगियों के साथ–साथ कांग्रेस को भी चुप कराने की रणनीतिक कवायद हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के पास अभी बहुमत का हिसाब नहीं है, तो यह नया मुहावरा एजेंडा निर्धारित करने की उनकी छवि को फिर से हासिल करने का प्रयास है। उन्होंने गंभीर सेकुलर चर्चा की जरूरत को रेखांकित कर भाजपा की एक प्रमुख मांग को कुछ समय के लिए परे रख दिया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया है या इसकी मंशा जतायी है।

संघ के बड़े नेता अपनी आंतरिक बैठकों में इस पर जल्दी कुछ करने का निवेदन कर रहे हैं। भाजपा के लोग इस सेकुलर कवायद को मोदी का मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। इसीलिए इस बात में दम दिखता है कि अपनी कई पहलों पर पैर पीछे खींचने वाली सरकार इस मुद्दे पर कुछ ठोस करना चाहती है। प्रारूप पर काम चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था क्योंकि भाजपा को प्रचंड बहुमत की आशा थी। सरकार को अपने सहयोगी दलों के विरोध के बाद वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। मोदी सरकार को लैटरल एंट्री के मामले में भी पीछे हटना पड़ा है। लैटरल एंट्री के तहत 45 अफसरों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस पर खूब विरोध हुआ। उसमें दिव्यांग लोगों के लिए एक श्रेणी थी। हाल के दिनों में इस श्रेणी में फर्जीवाड़े से भर्ती के अनेक मामले सामने आये हैं। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सरकार में लाने का यह विचार नीति आयोग का था, जिसने बिना आरक्षण के बड़ी संख्या में युवा पेशेवरों को भर्ती किया है। साल 2018 से 63 अधिकारियों को बिना आरक्षण के सीधे नियुक्त किया गया है। भाजपा को पूर्ण बहुमत था और विपक्ष मरणासन्न था, तो मोदी को इस मामले में कोई चुनौती नहीं मिली थी। लेकिन 2024 के जनादेश ने सत्ता के भगवा रंग को फीका कर दिया है। सहयोगी दल उन मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, जिनका उनके लिए वैचारिक महत्व है।

जैसे ही यह विज्ञापन आया, तो सबसे पहले विरोध के स्वर छोटे सहयोगी दलों के ही थे, कांग्रेस के नहीं। एलजेपी के चिराग पासवान ने इसे वापस लेने की मांग की। वे अपना वोट बैंक बनाये रखने और निर्णयों को प्रभावित करने की अपने पिता राम विलास पासवान की राजनीतिक रणनीति की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने वीपी सिंह को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने पर मजबूर किया था, जबकि वरिष्ठ पार्टी नेताओं और सहयोगियों की राय अलग थी। कुछ समय बाद वीपी सिंह का राजनीतिक अवसान हो गया, पर पासवान लंबे समय तक बने रहे। जद(यू) और तेलुगू देशम ने भी इस विज्ञापन को वापस लेने की सलाह दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संवैधानिक प्रावधानों को अनदेखा करने के लिए भाजपा की कड़ी निंदा की और सोशल मीडिया पर लिखा कि लैटरल एंट्री से खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है, पर भाजपा के लोग इसका खूब समर्थन कर रहे हैं। कुछ ही समय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दे दिया। पहली बार सरकार अपने ही निर्णय को वापस लेने के लिए सामाजिक न्याय का हवाला दे रही थी।मोदी के साथ सबसे अहम बात यह है कि उन्हें अपने निर्णयों की क्षमता पर पूरा भरोसा होता है। उनके लिए दबाव या डर से पीछे हटना कभी विकल्प नहीं रहा। हालिया महीनों में उनमें बदलाव देखा जा रहा है। उनके समर्थक अपने को यह कहकर सांत्वना दे रहे हैं कि माओ के 'एक कदम पीछे, दो कदम आगे' के सिद्धांत पर चलकर मोदी भविष्य में ताकतवर होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भले ही इस कोशिश में विचारों और विचारधारा से कुछ समय के लिए समझौता करना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मनिरपेक्षता को एक ज्वलंत मुद्दा बना दिया है और उस आग को भड़का भी रहे हैं। राख से ही फिनिक्स पैदा होता है।

कांग्रेस ने बड़ी लड़ाई गंवा दी

एस. सुनील

राजनीति और युद्ध के रणनीतिकार यह मानते हैं कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कई बार छोटे छोटे मुकाबले हारने होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो राजनीति की है उससे ऐसा लग रहा है कि उसने छोटा मुकाबला जीतने के लिए बड़ी लड़ाई गंवा दी है। उसने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फारूक और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से तालमेल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि यह तालमेल पार्टी के प्रभारी महासचिव या किसी और नेता ने की है। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद इसके लिए श्रीनगर गए थे। वे अपने साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को भी लेकर गए थे। खडग़े और राहुल ने स्वंय फारूक और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और तालमेल को अंतिम रूप दिया। तभी इसके आगे अब जो भी घटनाक्रम होगा उसकी जिम्मेदारी पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी की भी होगी।

सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब तालमेल किया उससे दो दिन पहले ही उस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र में कहा है कि वह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को फिर बहाल करेगी। उसने यह भी कहा कि वह अनुच्छेद 35ए को भी फिर से बहाल करेगी और विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण देने के प्रावधान को भी बदलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह घोषणापत्र आने के बाद राहुल गांधी ने उसके साथ तालमेल किया है। यह नहीं माना जा सकता है कि राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनावी घोषणापत्र नहीं देखा होगा। उन्होंने घोषणापत्र देखने के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ तालमेल किया है।इसलिए राहुल गांधी को निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 पर अपनी और पार्टी की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं और वे नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा इसे फिर से बहाल करने के वादे का समर्थन करते हैं या नहीं? ध्यान रहे अगस्त 2019 में जब संसद में प्रस्ताव पेश करके इस अनुच्छेद को समाप्त किया गया तो पूरे देश ने इसका स्वागत किया था। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन किया। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो उसने भी आधिकारिक रूप से इसका विरोध नहीं किया। उसके बाद से कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि वह जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराएगी। उसने कभी नहीं कहा कि वह विशेष राज्य का दर्जा बहाल कराएगी। इस तरह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए पर रणनीतिक रूप से समान दूरी का रवैया अपनाया हुआ है। वह इन दोनों अनुच्छेद को हटाने का न तो खुल कर समर्थन करती है और न खुल कर विरोध करती है।परंतु अब कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तालमेल किया है, जिसने अनुच्छेद 370 और 35ए की वापसी का वादा किया है। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा कि वह जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में क्या सोचती है? वह जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किए जाने के बारे में क्या सोच रखती है? राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के साथ घनघोर भेदभाव करने वाले अनुच्छेद 35ए के बारे में क्या सोचती है? जम्मू कश्मीर के अलग संविधान और अलग झंडे के बारे में क्या सोचती है? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान तो कांग्रेस से इन सवालों के जवाब मांगे ही जाएंगे उसके बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस को देश की जनता को इसका जवाब देना होगा, जिसने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का खुले दिल से स्वागत किया था। कांग्रेस इन सवालों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अगर वह जवाब नहीं भी देती है तब भी देश की एकता और अखंडता से जुड़े इस मसले पर उसकी सचाई जनता के सामने आ चुकी है।

हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तालमेल और इन गंभीर मुद्दों पर चुप्पी कांग्रेस को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुछ सफलता दिला दे लेकिन इन्हीं कारणों से कांग्रेस देश की लड़ाई गंवा देगी। कांग्रेस के प्रति देश भर में फिर से अविश्वास पैदा होगा। उसके विभाजनकारी एजेंडे पर नए सिरे से चर्चा होगी। यह आरोप प्रमाणित होगा कि वह जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनने के पक्ष में नहीं है। अगर नए सिरे से अनुच्छेद 370 और 35ए की बहस छिड़ती है तो संविधान में इन्हें शामिल कराने के जवाहरलाल नेहरू के फैसले की भी समीक्षा होगी। संविधान सभा की बहसों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य के प्रावधान का विरोध किया था। नागरिकों से भेदभाव करने वाले इन विशेष प्रावधानों को लागू करने के पक्ष में वे नहीं थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जिद के चलते इन्हें लागू किया गया। अगर भानुमति का पिटारा खुलता है तो नेहरू के समय इन विभाजनकारी संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनको हटाए जाने तक की समीक्षा होगी। इसमें कांग्रेस को कई ज्वलंत सवालों के जवाब देने होंगे।

यह ध्यान रखने की जरुरत है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से शांति स्थापित हुई है तीन दशक तक अशांत रहा यह प्रदेश देश की मुख्यधारा से जुड़ा है। इससे सीमा पार भी बेचैनी है और देश के अंदर भी अलगाववादी ताकतें इससे परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब छह साल के राष्ट्रपति शासन के दौरान विकास और सुरक्षा बढ़ाने वाले काम हुए हैं, जिससे नागरिकों में भरोसा बना है और वे लोकसभा चुनाव में खुल कर मतदान के लिए बाहर निकले। जम्मू कश्मीर के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि सभी पांच लोकसभा सीटों पर औसतन 50 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ। इसी वजह से चुनाव आयोग ने जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव में मतदान के आंकड़े सामने आने और चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए दूसरी ओर अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों की बेचैनी इतनी बढ़ी कि उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सिर्फ जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर 10 बड़े हमले हुए, जिसमें सैन्य अधिकारियों सहित 15 जवान शहीद हुए।यह इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाने, विकास की गति बढ़ाने और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार बनवाने की प्रक्रिया भारत विरोधी ताकतों को अच्छी नहीं लग रही है। वे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने में लगे हैं। ऊपर से घाटी में उग्र अलगाववादी विचारों वाली एक नई जमात तैयार हो रही है, जिसने लोकसभा चुनाव में जेल में बंद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को वोट देकर चुनाव जिताया।

राजपाल यादव की फिल्म पड़ गए पंगे का ट्रेलर आउट, फनी डायलॉग और कॉमेडी से है भरपूर

कॉमेडी फ़िल्म पड़ गए पंगे का बेहद फन्नी और एंटरटेनिंग ट्रेलर आउट कर दिया गया है जो सोशल मीडिया पर काफी लाइक किया जा रहा है। ट्रेलर में हम राजपाल यादव, राजेश शर्मा और पंचायत फ़ेम फ़ैसल मलिक के साथ ही इस फ़िल्म से डेब्यू कर रहे समर्पण सिंह और राजेश यादव को फनी रूप में देख सकते हैं।

ट्रेलर की शुरुआत होती हैं बेहद नाटकीय संवाद के साथ तरीके से समर्पण सिंह कहते हैं अलविदा ए ज़िंदगी और राजेश शर्मा कहते हैं हे ईश्वर मरणोपरांत हेम अपने श्री चरणों में स्थान दे देना । राजेश शर्मा और समर्पण सिंह आत्महत्या के लिए काउंटडाउन रुक जाता हैं जब राजेश शर्मा बताते हैं की 3 बजे आत्महत्या ठीक नहीं यह भूत प्रेत का समय होता हैं आत्मा सालों साल भटकती रहेगी कल मर लेते हैं । ट्रेलर के दूसरे हिस्से में आयुष (समर्पण सिंह) का इंट्रो सीन में शादी तय हो रही हैं और उनकी गर्लफ्रेंड हनीमून का वेन्यू के बारे में पूछ रही हैं तो उनके टीचर शास्त्री जी (राजेश शर्मा) का इंट्रो है की मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत हैं लेकिन घर में नहीं हैं फिर आते है जग्गू (राजेश यादव) आते हैं जो खुद को मनी एडवाइजर बताते हुए एक दिन में पैसा डबल करने की गारंटी देते हैं । ट्रेलर के अगले हिस्से में डॉक्टर आयुष और शास्त्री जी को बेहद ही अलग किस्म के कैंसर की बीमारी होने की बात बताते हुए 30 से 40 का खर्च बताया लेकिन यह 40 हज़ार नहीं बल्कि लाख हैं बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से ट्रेलर में यह सीन हँसाता हैं फिर राजपाल यादव आते हैं बोलते है यह सुनकर बहुत दुख हुआ ।

इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर आया रविचंद्रन अश्विन का रिएक्शन

नई दिल्ली। पहले मेगा ऑक्शन की संभावना है। लीग के 18वें सीजन की शुरुआत होने में अभी काफी समय है, लेकिन इस पर अभी से चर्चा शुरू हो गई है।

इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर एक्सपर्ट की राय अलग–अलग है। इस बीच अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी राय दी है। अश्विन का मानना है कि यह नियम रहना चाहिए। कं रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे।

इतना बुरा भी नहीं है रूल

क्रिस श्रीकांत के यूट्यूब शो चीकी चीका पर अश्विन ने इम्पैक्ट प्लेयर नियमों के लाभों के बारे में बताया। अश्विन का कहना है कि ऑलराउंडर्स को अच्छा प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। अश्विन ने वेंकटेश अय्यर का उदाहरण दिया।

विश्व कप विजेता भारतीय कप्तान के दिल में था छेद

नई दिल्ली। भारतीय अंडर–19 टीम के कप्तान रहे यश धुल दिल की सर्जरी के बाद वापसी कर चुके हैं। उनके कोच राजेश नागर ने पीटीआई को बताया कि एनसीए में अंडर–23 हाई परफॉर्मेंस कैंप के दौरान जब नियमित स्कैन किया गया तो धुल के दिल में एक छोटा सा छेद पाया गया।

कोच ने दिया फिटनेस अपडेट

नागर ने बुधवार को कहा, "यह कोई बड़ी सर्जरी नहीं थी। उन्हें ठीक होने में करीब 10 से 15 दिन लग गए। वह अपने खेल और फिटनेस के मामले में इस समय 100 प्रतिशत नहीं हैं, मैं कहूंगा कि वह लगभग 80 प्रतिशत फिट हैं, लेकिन काफी अच्छे हैं।" यश धुल दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए खेल रहे हैं। पांच पारियों में उन्होंने 113.41 के स्ट्राइक रेट से कुल 93 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 52 रन रहा है।

घरेलू क्रिकेट में यश धुल का प्रदर्शन

यश धुल की कप्तानी में 2022 में भारत ने अंडर–19 का खिताब अपने नाम किया था। घरेलू क्रिकेट में यश धुल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक 23 फर्स्ट क्लास मैच

खेले हैं। इस दौरान 40 पारियों में उन्होंने 44.72 की औसत और 67.42 की स्ट्राइक रेट से 1610 बनाए हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 5 अर्धशतक और 5 शतक लगाए हैं। 19 लिस्ट ए मैच की 16 पारियों में उन्होंने 49.00 की औसत और 88.55 की स्ट्राइक रेट से 588 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम 2 अर्धशतक और एक शतक दर्ज है। टी20 में यश धुल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 19 मैच की 18 पारियों में 588 रन बनाए हैं।

दूसरे संडे कमाई में हुआ मामूली इजाफा, फिर भी डिजास्टर बनीं अक्षय–जॉन की फिल्में

पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2, खेल–खेल में और वेदा का महाक्लैश हुआ था. हालांकि तीनों फिल्में एक ही दिन 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुईं लेकिन सबसे ज्यादा फायदा श्रद्धा कपूर–राजकुमार राव की फिल्म को हुआ. स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही कब्जा जमा लिया और अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा का बुरा हाल कर दिया. हालांकि, अक्षय कुमार की खेल खेल में ने पिछले कुछ दिनों में जॉन अब्राहम की वेदा को पछाड़ते हुए बढ़त हासिल की है. चलिए यहां जानते हैं इन दोनों फिल्मों ने रिलीज के 11वें दिन कितना कलेक्शन किया है?स्त्री 2 अक्षय कुमार स्टारर खेल खेल में पर कहर बनकर टूट रही है और फिल्म को कमाई का मौका नहीं दे रही है. उम्मीद थी की खेल खेल में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी लेकिन रिलीज के पहले दिन ही इसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. फिल्म एक भी दिन डबल डिजीट में कमाई नहीं कर पाई और अब तो खेल खेल में मुश्किल से चंद करोड़ कमा पा रही है. 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है और इसके लिए आधा बजट निकालना भी बेहद मुश्किल हो गया है.

खेल खेल में की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 19.35 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं अब ये रिलीज के दूसरे हफ्ते हैं और इसने दूसरे फ्राइडे जहां 70 लाख कमाए तो दूसरे शनिवार फिल्म की कमाई में 92.86 फीसदी की तेजी आई और इसने 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं अब इस फिल्म की रिलीज के दूसरे संडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ह्यखेल खेल मेंह्व ने दूसरे संडे 1.75 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ खेल खेल में का 11 दिनों का कुल कलेक्शन अब 23.15 करोड़ रुपये हो गया है.

कंगना रनौत की इमरजेंसी का पहला गाना सिंहासन खाली करो जारी

कंगना रनौत स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी का पहला गाना सिंहासन खाली करो रिलीज हो गया है. हाल ही में सॉन्ग सिंहासन खाली करो का टीजर जारी कर इसकी रिलीज डेट का एलान किया गया था. सिंहासन खाली करो में फिल्म इमरजेंसी की पूरी स्टारकास्ट नजर आ रही है. सिंहासन खाली करो सॉन्ग एक जज्बे और जोश से भरा गाना है. सिंहासन खाली करो गाना फिल्म की रिलीज से 10 दिन पहले रिलीज हुआ है. सॉन्ग सिंहासन खाली करो को उदित नायाराण, नकाश अजीज, नकुल अभयंकर ने मिलकर गाया है. सिंहासन खाली करो गाने के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. गाने को जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किया है. गाने में कंगना रनौत, अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक भी नजर आ रहे हैं. कंगना रनौत को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के रोल में देखा जा रहा है. गाने में इमरजेंसी लगने के बाद के सीन दिखाए जा रहे हैं, जिसमें विपक्ष और आम जनता पर पुलिस की लाठी बरस रही हैं.

शिखर धवन–दिनेश कार्तिक की होगी वापसी, 6 टीमों के बीच खेले जाएंगे 25 मुकाबले

नई दिल्ली। लीजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत 20 सितंबर को जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में होगी। लीग के तीसरे सीजन में 6 टीमों के बीच 25 मुकाबले खेले जाएंगे। टॉप–2 टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 16 अक्टूबर को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगा। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले शिखर धवन और इस साल की शुरुआत में क्रिकेट को अलविदा कहने वाले दिनेश कार्तिक अब लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। लगभग 40 साल

बाद दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर श्रीनगर में खेलते दिखेंगे।

कश्मीर में 40 साल बाद होगा क्रिकेट

लीग के सभी मुकाबले श्रीनगर, जोधपुर और सूरत में खेले जाएंगे। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के को फाउंडर रमन रहेजा ने कहा, "लीजेंड्स लीग क्रिकेट एक और सीजन के लिए वापस आ गया है। हम इस सीजन में कश्मीर में खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। यह कश्मीर के लोगों के लिए स्टेडियम में आने और लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाइव क्रिकेट एक्शन देखने का एक बड़ा अवसर है।"

गुरुवार को होगी नीलामी

उन्होंने कहा, "यह क्रिकेटरों के लिए कश्मीर की सुंदरता का अनुभव करने और श्रीनगर के लोगों के प्यार का आनंद लेने का अवसर है।"आयोजकों ने बताया कि लीग के पिछले सीजन में खेले गए 19 मैचों को 18 करोड़ लोगों ने देखा था। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन में सुरेश रैना, आरोन फिंच, मार्टिन गुप्टिल, गौतम गंभीर, क्रिस गेल, हाशिम अमला, रॉस टेलर समेत 110 दिग्गज क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया था।

लीग जोधपुर में शुरू होगी और फिर सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में पहुंचेगी। तीसरा चरण जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में खेला जाएगा।

एक नजर

दस खाद्य कारोबारियों के खिलाफ वाद दायर

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद में दस खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और नियम विनियम 2011 का उल्लंघन पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया है। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि अगस्त माह में अभी तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कुल 10 मामलें न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी के न्यायालय में दायर किए गए हैं।

जिला अभिहित अधिकारी एएस रावत ने बताया कि जिले की यमकेश्वर तहसील में बीते दिनों हुए कांवड़ मेले के दौरान एक्सपायरी शीतल पदार्थ बिक्री के लिए रखने, भंडारण करने पर संबंधित खाद्य एक कारोबारी के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। बताया कि बिना पंजीकरण लाइसेंस के समान बिक्री करने पर एक खाद्य कारोबारी के खिलाफ भी वाद दायर किया गया। अभिहीत अधिकारी ने बताया कि कोटद्वार तहसील के एक खाद्य कारोबारी के खाद्य नमूनों के परिणाम मिस ब्रांड (मिथ्या छाप) पाए जाने पर खाद्य कारोबारी पर वाद किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी जिले के अन्य स्थानों पर स्थित सात मीट विक्रेताओं की दुकान पर साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मीट विक्रेताओं को प्रमाण पत्र न देने पर खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के तहत अपर जिला अधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं।

जल भराव की समस्या से निजात दिलाए नगर निगम

ऋषिकेश। गंगानगर में जल भराव की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने नगर आयुक्त से समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग की। बुधवार को गंगानगर के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सभासद बृजपाल राणा ने कहा कि वर्ष 2023 के अगस्त माह में हनुमन्तपुरम गंगानगर क्षेत्र में बरसात के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिसमें काफी नुकसान क्षेत्रवासियों का हुआ। इसके बाद क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार धरना–प्रदर्शन और अधिकारियों से पत्राचार किया गया। इसके बाद कुछ अस्थाई समाधान जैसे नालों और नालिया की सफाई आदि कार्य किए गए। लेकिन इसका अभी तक स्थाई समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में अभी भी बरसात के दौरान क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन रही है। इसलिए किसी विशेषज्ञ एजेंसी से संपूर्ण गंगानगर क्षेत्र का सर्वे करवाकर इसका समाधान करवाया जाए। मौक पर प्यारेलाल जुगराण, आशीष कुमार, भोपाल सिंह नेगी, मनोज काला, मानवेंद्र सिंह भंडारी, पंकज अरोड़ा, राधेलाल गौड़, सौरभ कालडा, दर्शन सिंह रावत, भागवत पांडे, शैलेंद्र भंडारी आदि उपस्थित रहे।

हर बूथ में 200 प्राथमिक सदस्य बनेंगे

ऋषिकेश। एक सितंबर से रानीपोखरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होगा, जिसके लिए भाजपाईयों ने बैठक कर रणनीति बनाई। जिसमें प्रत्येक बूथ पर दो सौ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। बुधवार को रानीपोखरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की।

सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : रिखणीखाल में आयोजित भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। आयोजित बैठक का शुभारंभ लैंसडौन विधायक दिलीप सिंह रावत, मुख्य वक्ता जगमोहन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा कि हमें प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। कहा कि प्रत्येक कार्यकर्त्ता का लक्ष्य संगठन में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना होना चाहिए।

रिखणीखाल ब्लाक सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते विधायक दिलीप सिंह रावत

उन्होंने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कहा कि वह लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य वक्ता जगमोहन सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और इस विचार को हमें घर-घर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम सह संयोजक मोहन सिंह नेगी ने कहा कि गरीब व असहाय परिवारों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हम सभी को एकजुट होकर इन योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर रिखणीखाल मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, जिला मीडिया प्रभारी विनोद रावत, किसान मोर्चा महामंत्री दिनेश रावत, जिला पंचायत सदस्य विनय पाल सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य शालिनी बलोधी, गोवर्धन प्रसाद टम्टा, सैन सिंह रावत, चंद्रशेखर ध्यानी, बृजमोहन देवरानी, सनोज रावत, अनिल ध्यानी, तारा सिंह, सुभाष सिंह, भारत सिंह रावत, दीपक गुसाईं, अनिल रावत, नरेंद्र सिंह रावत, रमेश रावत, देवेंद्र पाल सिंह नेगी, विपिन मेंदोला आदि मौजूद रहे।

बलूनी पब्लिक स्कूल रहा विजयी

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : बलूनी पब्लिक स्कूल की ओर से खेल रत्न मेजर ध्यान चंद की स्मृति में स्कूल प्रांगण में बालक-बालिकाओं की त्रिदिवसीय अंतर्विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता बुधवार से आरंभ हो गई है। प्रतियोगिता का आरंभ बलूनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन बलूनी, बलूनी क्लासेस की मैनेजिंग डायरेक्टर अभिलाषा भारद्वाज, विद्यालय प्रधानाचार्य जूही नेगी द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस बुधवार को बालिका वर्ग के मैच खेले गए। बलूनी पब्लिक स्कूल-2 ने हैप्पी होम, एवीएन स्कूल ने राइजिंग सन, डीएवी ने स्कालर्स एकेडमी, एसजीआरआर ने बलूनी पब्लिक स्कूल 1, नवयुग ने मदरलैंड, बलूनी पब्लिक स्कूल-2 ने आरपी स्कूल, एवीएन ने एसजीआरआर और डीएवी पब्लिक स्कूल ने डैफोडिल्स को हराया।

ठेकेदारों ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को लोनिवि कार्यालय में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित ठेकेदारों ने अपनी 19 सूत्रीय मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति ने लोनिवि प्रांतीय खंड के कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान समिति के सचिव प्रदीप असवाल, सुनील नेगी, खुशाल सिंह नेगी, आशीष थपलियाल आदि ने कहा कि पिछले लंब समय से ठेकेदार विभिन्न समस्याओं के हल की मांग कर रहे है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने 10 करोड़ तक के काम प्रदेश के लोगों को ही देने, निविदा में स्थाई व मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता करने, 5 करोड़ तक के कार्य सिंगल ब्रिड सिस्टम से करने, केंद व राज्य सरकार के बजट के 80 फीसदी तक के निर्माण कार्य प्रदेश के ही ठेकेदारों को देने, बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में बदलने का अधिकार खंडीय कार्यालय के अधिशासी अभियंता को देने की मांग उठाई।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

1	**कार्य का नाम एवं लोकेशन : 14/वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा./2024 दूसरी कॉल:-** मुरादाबाद मंडल में विभिन्न स्थानों पर स्थापित यूटीएस और पीआरएस, बैटरी बैंक के साथ विभिन्न निर्माण और क्षमताओं के ऑन लाइन यूपीएस के तीन (3) वर्षों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव के लिए अनुबंध।
2	**कार्य की अनुमानित लागत (रु.) :** 56,23,105.36 (जीएसटी सहित)
3	**कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र जारी किया गया है :** विद्युत शाखा, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
4	**बिड सिक्यूरिटी राशि (रु.) :** 1,12,500/-
5	**कार्य के पूर्ण करने की समय अवधि :** 36 (छत्तीस) माह
6	**निविदा प्रपत्र जमा करने तथा खुलने की दिनांक व समय :** निविदायें दिनांक 13.09.2024 को 15.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 15.00 बजे खोली जायेगी।
7	**वेबसाइट एवम कार्यालय का पता :** वेबसाइट www.ireps.gov.in मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय / उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

निविदा सूचना सं.: 20/2024 दिनांक: 22.08.2024 **2652/2024**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

विद्यालयों में नहीं हैं पर्याप्त शिक्षक, भड़का अभिभावकों का गुस्सा

शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना देते अभिभावक

प्रखंड बीरोंखाल के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर किया प्रदर्शन

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : पहाड़ों के विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती नहीं होने पर अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा। प्रखंड बीरोंखाल में शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि लाख शिकायतों के बाद भी विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा रही है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर विद्यालयों में तालाबंदी की चेतावनी दी है।

ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी के नेतृत्व में अभिभावकों व ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना दिया। कहा कि एक ओर ग्रामीणों ने कहा कि एक ओर शिक्षा विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे कर रहा है। वहीं, पहाड़ों में शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहा कि शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि अक्टूबर तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो ग्रामीण व जनप्रतिनिधि आंदोलन करते हुए विद्यालयों में तालाबंदी करेंगे। इस मौके पर ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप नेगी, विनोद नेगी, जयदीप नेगी, दिनेश चंद्र, गबर सिंह रावत, हरीश चंद्र, त्रिलोक सिंह, देशबंधु बिष्ट, जितेन्द्र कोहली, भूपेन्द्र सिंह रावत, हरेंद्र सिंह रावत, अरुण सिंह, सुरेन्द्र कुमार, विक्रम सिंह रावत, रणवीर बिष्ट, श्रीमती ज्योति देवी, लक्ष्मी देवी, सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, सुप्रिया मंडल, शकुंतला देवी, ग्राम पंचायत प्रधान धर्मेंद्र प्रसाद, विष्णु रावत, वंदना देवी, दीपा देवी, इंद्रपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, मीनाक्षी देवी, सुनील कुमार, श्रद्धानंद बौड़ाई, रमेश रावत, बलबीर रावत, राकेश जोशी आदि मौजूद रहे।

राधेलाल कुकरेती बने ऐसोसिएशन के अध्यक्ष

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : श्री गुरु राम राय इंटर कालेज दिउला पौखाल में अभिभावक/अध्यापक एसोशिएसन की पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान राधेलाल कुकरेती को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई।

प्रधानाचार्य प्रदीप बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष राधेलाल कुकरेती, कोषाध्यक्ष पूनम डबराल, उपमंत्री डा. शशिभूषण अमोली को चुना गया।

इस दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति की भी कार्यकारिणी गठित की गई। कार्यकारिणी में रंजू देवी को अध्यक्ष और आरती देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। साथ ही पूजा देवी, कुसुम देवी, समित्रा देवी, सपना देवी को कार्यकारिणी में बतौर सदस्य चुना गया। इस मौके पर मस्तान सिंह रावत, आनंद सिंह, किरण कुकरेती, रामेश्वरी देवी आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन विद्यालय के प्रवक्ता डा. शशिभूषण अमोली ने किया।

।। कार्यालय :- नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) ।।

पत्रांक :- 1650 /कर अनु0/भव0ना0/2024-25 दिनांक :- 28.08.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा नगर निगम कोटद्वार के भवन कर अभिलेखों पूर्व भवन स्वामी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करने हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्रों एवं शपथ पत्र आदि के आधार पर आवेदन किया गया है।

अतः नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 213(ख) के अन्तर्गत समस्त प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को निम्न नामान्तरण/नामान्तरणों पर आपत्ति हो वह मय साक्ष्यों को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। मियाद समाप्त होने पर उपलब्ध अभिलेखिया साक्ष्यों के आधार पर सम्पत्ति के नामान्तरण हेतु निर्णय पारित कर लिये जायेंगें।

क्र0 सं0	सम्पत्ति संख्या एवं मौहल्ले/वार्ड का नाम	भवन कर अभिलेखों में दर्ज नाम (नाम जो निरस्त होना है)	आवेदक का नाम व पता (नाम जो दर्ज होना है)	सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का आधार
1	2	3	4	5
1	141/108ए वार्ड 11 मालवीय उद्यान	श्री विनोद कुमार कण्डवाल पुत्र स्व0 श्री मनमोहन कण्डवाल	श्री ईशानदत्त कण्डवाल पुत्र श्री विनोद कुमार कण्डवाल	दाननामा रजिस्ट्री एवं शपथ पत्र
2	226/2/4 वार्ड 04 गाडीघाट	श्री सरस्वती देवी पत्नी श्री रामकृपाल सिंह	श्री हरिपाल पुत्र श्री पुरई	उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार।
(0399/51)

पूर्व पार्षद पर लगाया सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप

खूनीबड़ स्थित आवास में गुंबदनुमा आकृति बनाने का मामला

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : खूनीबड़ में एक आवास पर गुंबदनुमा आकृति बनाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालत यह है कि दो दिन पूर्व जहां एक समुदाय की महिला ने जनप्रतिनिधियों पर उसे धमकी देने का आरोप लगाया था। वहीं, अब कांग्रेस भी महिला के समर्थन में आ चुकी है। कांग्रेस ने क्षेत्र के एक पार्षद पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। कहा कि शासन-प्रशासन को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए।

कोटद्वार में उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी को ज्ञापन देते कांग्रेसजन

बुधवार को कांग्रेसी तहसील परिसर में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने जिलाधिकारी सोहन सिंह नैनी को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष विनोद डबराल व रश्मि पटवाल ने कहा कि भाबर क्षेत्र में रहने वाली हसीना बेगम के पति वर्तमान में सीआरपीएफ में तैनात हैं उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ में है। जबकि उनका पुत्र पैरा कमांडो है और उसकी तैनाती सिलांग में तैनात है। हसीना बेगम अपना दो मंजिला मकान बना रही थी। लेकिन, कुछ दिन पूर्व मकान के ऊपर गुबंदनुमा निर्माण को मस्जिद बताकर उसका विरोध किया गया। हसीना बेगम ने क्षेत्र के लोगों के विरोध के बाद पुलिस की मौजूदगी में उक्त गुबंदनुमा निर्माण को तोड़ दिया। कहा कि पूर्व पार्षद हसीना बेगम की छवि को खराब कर क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने हसीना बेगम सहित स्वजनों को सुरक्षा दिए जाने व आरोपित पूर्व पार्षद पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मौके पर रंजना रावत, बलवीर सिंह रावत, जसवीर राणा, गोपाल सिंह गुसांई, दलीप सिंह रावत, कृपाल सिंह नेगी, गबर सिंह, हसीना बेगम, प्रवेश रावत मौजूद रहे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कोटद्वार

अल्पकालीन निविदा सूचना

पत्रांक 1591 / निविदा / / 2024-25 दिनांक 27/08/2024

मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून की ओर से पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 03.09.2024 की पूर्वान्ह से 10.09.2024 की अपराह्न 5:00 बजे तक निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त की जा सकती है। निविदाएं दिनांक 11.09.2024 को सांय 3.00 बजे तक शाखा कार्यालय में निविदा बॉक्स में जमा की जा सकेगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। किसी भी तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस में मान्य होगा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य अवधि	निविदा का कुल मूल्य कर सहित	धरोहर धनराशि	ठेकेदार की पंजीकरण श्रेणी
1	हल्दूखाता नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित लूथापुर नलकूप में पम्प हाउस निर्माण एवं पाईप लाइन बिछाये जाने सम्बन्धी कार्य।	90 दिन	रू0 1500.00 +GST	23000.00	D या उच्चतर
2	मोटाढाक नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित देवरामपुर नलकूप में पम्प हाउस निर्माण एवं पाईप लाइन बिछाये जाने सम्बन्धी कार्य।	90 दिन	रू0 1500.00 +GST	32500.00	D या उच्चतर
3	सिगड्डी नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित श्रीरामपुर नलकूप में पाईप लाइन बिछाने एवं तत्सम्बन्धी कार्य।	30 दिन	रू0 500.00 +GST	2700.00	D या उच्चतर
4	सनेह नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित नाथूपुर (रामपुर) नलकूप में पाईप लाइन बिछाने एवं तत्सम्बन्धी कार्य।	30 दिन	रू0 500.00 +GST	6500.00	D या उच्चतर
5	कोटद्वार सीवरेज योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन जीर्णोद्वार का कार्य।	60 दिन	रू0 1500.00 +GST	42500.00	D या उच्चतर

शर्तेः- 1- कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के साइट इन्चार्ज के निर्देशानुसार करना होगा।
2- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
3- कार्य पूर्ण के 01 वर्ष पश्चात ही धरोहर राशि वापस की जायेगी।
4- ठेकेदार द्वारा लिफाफे पर योजना का नाम एवं ठेकेदार का पता अंकित होना अनिवार्य है।
5- निविदा क्रय करते समय विभागीय पंजीकरण की मूलप्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य है, जिसके अभाव में निविदा निर्गत नहीं की जायेगी।
6- निविदा के साथ जी0एस0टी0 प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7- अधोहस्ताक्षरी को किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
8- निविदा प्रपत्र के साथ 02 प्रतिशत धरोहर राशि, एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के रूप में अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोटद्वार के पक्ष में बंधक बनाकर निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
9- निविदा प्रपत्र के साथ 100/- का स्टाम्प पेपर जिस पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
10- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11- कार्यस्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त ही निविदा क्रय करें।
12- कार्य हेतु शेष शर्ते निविदा प्रपत्र पर दी गई शर्तों के अनुसार होगी।
13- निर्धारित अवधि के अन्दर ही कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा।
14- अनुबन्धित फर्म /ठेकेदार द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने पर फर्म को विभाग द्वारा एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में सम्बन्धित फर्म की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
15- पम्प हाउस निर्माण हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान/उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सिविल कार्यों में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

अधिशासी अभियन्ता
(0398/59)

समस्याओं पर भड़का ठेकेदार संघ, जल्द निराकरण की मांग

मांगों को लेकर प्रदर्शन करते ठेकेदार संघ के सदस्य

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : अपनी विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर ठेकेदार संघ पीडब्लूडी ने रोष व्यक्त किया है। कहा कि अतिरिक्त रायल्टी पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर वह कई माह से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन, अब तक समस्याओं के निराकरण को लेकर ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार संघ ने मांगें पूरी नहीं होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

प्रदीप नेगी के नेतृत्व में संघ से जुड़े ठेकेदार कार्यालय में एकत्र हुए व प्रदर्शन किया। कहा कि ठेकेदारों ने कहा कि आनलाइन बड़ी-बड़ी निविदाएं डाल कर बाहरी राज्यों के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय ठेकेदारों को भी काम मिल सके, इसके लिए छोटी-छोटी निविदाएं डाली जानी चाहिए। पंजीकरण से पूर्व साल्वेंसी व टेक्निकल स्टाफ की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य समाप्त नहीं करने पर पैनल्टी का प्रावधान है। लेकिन, कार्य पूर्ण होने के बाद भी विभाग समय पर भुगतान नहीं करता। ऐसे में विभाग को ब्याज सहित पैसे का भुगतान किया जाना चाहिए। आपदा व अनुरक्षण मद में किए गए कार्य का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। आपदा कार्यों में ठेकेदार की ओर से उपयोग की जा रही मशीन, सामग्री व लेबर का आंकलन कर उनका बीमा कवर विभाग के द्वारा दिया जाना चाहिए। प्रदेश के सभी विभागों की कार्यदायी संस्थाओं की नियमावली एक प्रदेश एक नियम के तहत होनी चाहिए। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह नेगी, मुकेश पोखरियाल, आलम सिंह रावत, देवेंद्र सिंह कंडारी, सुरेंद्र सिंह कंडारी, कुलदीप सिंह बंगारी, राजेश सिंह आदि मौजूद रहे।

विहिप का स्थापना दिवस 31 को

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : विश्व हिंदू परिषद स्थापना के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में परिषद की स्थानीय इकाई की ओर से 31 अगस्त को पदमपुर सुखरौ स्थित एक बारातघर के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

कार्यक्रम में प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार मुख्य वक्ता और शंकरमठ आश्रम रुड़की के पीठाधीश्वर दिनेशानंद भारती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। यह जानकारी बुधवार को विहिप जिला सह मंत्री सचिन नेगी ने दी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री आरवी का जन्म दिनांक 16-01-2019 को हुआ है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम अस्मिता दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही व वास्तविक नाम आरवी है। मेरी पुत्री को आरवी नाम से जाना, पहचाना जाये।

विकास कुमार पुत्र विरेश कुमार निवासी शिवपुर, सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

(0397/21)

एक नजर

राजकीय प्रधानाचार्य संगठन भी उतरा विरोध में

देहरादून। राजकीय प्रधानाचार्य संगठन ने प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का विरोध किया किया है। संघ ने इसे शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति के अधिकारों का हनन बताया है। इस संबंध में बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज सौडा सरोली में अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को आंदोलन के लिए चेताया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग की सीधी भर्ती उपखंड शिक्षा अधिकारी से निर्धारित की जाती है और उसके ऊपर के पदों पर नियमावली के तहत वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है, उसी प्रकार से प्रधानाचार्य से पूर्व का पद प्रधानाध्यापक के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरने की व्यवस्था की जाए।

स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को मुफ्त परामर्श

देहरादून। विश्व फिजियोथैरेपी माह के तहत नव्य भारत फाउंडेशन एवं स्टूडेंट असोसिएशन ऑफ फिजीकल थैरेपी की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर नव्य भारत चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर, बालावाला में आयोजित किया गया। जिसमें पीजीआई चंडीगढ के डाक्टरों ने मुफ्त परामर्श एवं दवाएं दी। मुख्य अतिथि मेजर जनरल (रिटा.) कुवंर दिग्विजय सिंह ने किया। डॉ. बिबेक आध्या, डा. हर्ष कुंवर, डॉ. आशीष पाल ने सेवाएं दी और खून की जांच मुफ्त कराई गई। एनबीएफ एवं एसएपीटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिरुद्ध उनियाल, देवानंद डोभाल, प्रेमा उनियाल, खेमराज उनियाल, अजय उनियाल, प्रमिला उनियाल, सिमरन कौर , अभिजीत उनियाल आदि मौजूद रहे।

केवि आईएमए और आर्मी स्कूल सेमीफाइनल में पहुंचे

देहरादून। छठवीं एसपी सिन्हा मेमोरियल अंडर 19 इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता में केवि आईएमए और आर्मी स्कूल ने सेमीफाइल में जगह पक्की की। बुधवार को इंडियन पब्लिक राजवाला मैदान पर मुकाबले हुए। स्कूल के हेड ऑफ स्पोर्ट्स अरुण गुसाईं ने बताया कि पहले क्वार्टर फाइनल में केवि आईएमए का सामना ब्रिस्टल स्कूल से हुआ। इसमें केवि आईएमए ने 3–0 से एक तरफ जीत दर्ज की। केवि आईएमए के लिए दिव्यांश ने छठवें, नयाल ने 16वें और 45वें मिनट में गोल दागा। दूसरे क्वाटर फाइनल मैच में वाइन बर्ग एलन स्कूल मसूरी को आर्मी पब्लिक स्कूल क्लेमनटाउन ने 3–0 हराया। आर्मी स्कूल के लिए प्रिंस नेगी ने 14वें व 60वें और आर्यन ने 68वें मिनट में गोल किया।

विरोधः दो सितंबर को चौक डाउन करेंगे शिक्षक

देहरादून। शिक्षक संगठनों ने प्रदेश में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती का विरोध किया है। इसके साथ ही राजकीय शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संघ का कहना है कि यदि सरकार 30 अगस्त तक इस आदेश का निरस्त नहीं करती है तो संघ दो सितंबर से आंदोलन शुरू कर देगा। दो सितंबर से शिक्षक विद्यालयों में चौक डाउन करेंगे। इस संबंध में बुधवार को डायट देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष और मंत्री ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इसमें तहत एक 30 अगस्त को दोनो मंडल अपने जनपदों में बैठक करेंगे। जबकि, दो सितंबर को विद्यालय में चौक डाउन की जाएगी। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, छह सितंबर को जिला मुख्यालयों में सभी शिक्षक व्यक्तिगत अवकाश (सीएल) लेकर आंदोलन करेंगे।

हेस्को हिमालय दिवस को सप्ताह के रूप में मनाएगा

देहरादून। हैस्को ने इस बार हिमालय दिवस के कार्यक्रमों का विषय ह्यहिमालय की दिशा व दशा पर केंद्रित किया है। नौ सितंबर को आयोजित होने वाले हिमालय दिवस के कार्यक्रम दो सितंबर से शुरू हो जाएंगे। यह जानकारी हैस्को की ओर से पदमभूषण डॉ.अनिल प्रकाश जोशी ने साझा की है। डॉ. जोशी ने बताया कि दो सितंबर से नौ सितंबर तक विभिन्न संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को हिमालय के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से हिमालय दिवस का आयोजन करने के साथ ही उसमें भागेदारी कर हिमालय के प्रति अपनी श्रद्धा और सोच को आगे बढ़ाते हुए इसमें भागेदारी की अपील की है। हेस्को के संस्थापक पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने बताया कि इस बार नौ सितंबर को हिमालय दिवस का विषय हिमालय दिशा और दशा पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री धामी ने किया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं प्लास्टिक की बोतल को बार कोड से स्कैन कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक की खपत को कम करने एवं अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकल कर, उसे इस्तेमाल में लाने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफन्ड सिस्टम का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा डिजिटल डिपॉजिट रिफन्ड सिस्टम को धरातल में उतारने के लिए समन्वय से कार्य किये जाएं। यह पहल चार धाम यात्रा एवं अन्य पर्यटन स्थलो में भी कूड़े की खपत को कम करते हुए स्वच्छता का वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक की समस्या संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती बन गई है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों में प्लास्टिक की बड़ी समस्या के तौर पर सामने आती है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। राज्य में स्वच्छता का वातावरण बनाते हुए क्लीन उत्तराखंड, ग्रीन उत्तराखंड पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। राज्य की प्राकृतिक संपदा हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है, इसको सुरक्षित रखना भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल डिपोजिट रिफन्ड सिस्टम को 2 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखंड में लाया गया था। जिसके सफल संचालन के लिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा नदियां, जंगल, पहाड़ राज्य की धरोहर और पहचान है। प्लास्टिक हमारी इन धरोहरों को खतरे में डाल रही है। जिसके निस्तारण के लिए राज्य सरकार विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। जिससे भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में नई क्रांति का संचार हुआ था। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की स्वच्छता के लिए अनेक कार्य हो रहे हैं।

इस अवसर पर जानकारी दी गई कि डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण सरल हो जाएगा। डी.डी.आर.एस के तहत प्लास्टिक बोतल/प्लास्टिक पदार्थों का उत्पादन करने वाली ईकाईयों द्वारा ह्लक्यूआर कोड सिस्टम जनित किया जायेगा, जिससे उपभोगताओं द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग में भण्डारित पदार्थों का प्रयोग करने के पश्चात् प्लास्टिक अपशिष्ट को नज़दीकी डी.डी.आर.एस सेंटर को वापस किया जायेगा व बार कोड स्कैन करने के पश्चात् उपभोगता को प्रत्येक प्लास्टिक अपशिष्ट पर एक निश्चित धनराशि वापस की जायेगी।

डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के लागू होने से प्लास्टिक कचरे को सर्कुलर इकोनॉमी में वापस लाया जा सकेगा, जिससे संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

निगम कर्मचारी महासंघ को सीएम का आश्वासन, जल्द होगा डीए का भुगतान

देहरादून। निगमों के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ जल्द मिलेगा। बुधवार को सचिवालय में राज्य निगम कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता में आश्वासन दिया। सीएम ने सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग विनय शंकर पांडेय को जल्द बढ़ा हुए डीए सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। सचिवालय में हुई वार्ता में अध्यक्ष राणाकोटी ने सीएम को बताया कि जनवरी 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ निगम कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है। जबकि राज्य कर्मियों को ये लाभ काफी पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। निगम कर्मचारियों को हर बार सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हर बार निगम कर्मचारियों को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए बेवजह के चक्कर कटवाए जाते हैं। जबकि सरकार की ओर से कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य कर्मियों के लिए जारी होने वाले आदेशों का लाभ सीधे निगम कर्मियों को भी उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद भी शासन स्तर पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

सीएम धामी ने महासंघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि निगम कर्मचारियों को समय पर सभी लाभ सुनिश्चित कराए जाएंगे। डीए का भुगतान जल्द होगा। भविष्य में निगम कर्मचारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वार्ता में अजयकांत शर्मा, ललित शर्मा, अरविंद पयाल, नंदलाल जोशी आदि मौजूद रहे।

सार्वनिक उद्यम ब्यूरो का गठन कर समाप्त हो भेदभाव

निगम, निकाय समेत स्वायत्तशासी संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को राज्य में अलग से एक सार्वनिक उद्यम ब्यूरो के गठन की भी मांग की गई। ताकि निगम कर्मचारियों को भी राज्य कर्मियों की तरह सभी लाभ एकसमान रूप से समय पर मिल सके।

निगम संविदा कर्मियों का तत्काल हो नियमितीकरण

महासंघ पदाधिकारियों ने सीएम से संविदा, आउटसोर्स, उपनल कर्मचारियों को जल्द नियमित किए जाने की मांग की। अध्यक्ष राणाकोटी ने कहा कि हाईकोर्ट के नियमितीकरण से जुड़े आदेशों को तत्काल लागू किया जाए।

अन्य प्रमुख मांगे

–जल संस्थान कर्मियों को हाईकोर्ट के आदेश पर पेंशन का लाभ मिले।

–जीएमवीएन में एसीपी और स्टाफिंग पैटर्न का लाभ लागू हो।

–रोडवेज में एक मई 2022 के बाद के मृतक आश्रितों को भी नियमित सेवा प्रदान की जाए।

–वर्ष 1996 से स्वजल में कार्यरत कर्मचारी किए जाएं नियमित।

–दुग्ध विकास संघ कर्मचारियों को मिले डीए और सातवें वेतनमान का लाभ।

–वन विकास निगम में अधिकारियों की कमी को पूर्व की तरह प्रतिनियुक्ति से दूर किया जाए। –रोडवेज में खाली पदों पर तेजी से चले भर्ती अभियान।

गढ़वाल सभा ने सामुदायिक विकास भवन निर्माण के लिए किया भूमि पूजन

देहरादून। अखिल गढ़वाल सभा हरिपुर नवादा में सामुदायिक विकास भवन बनाने जा रहा है। बुधवार को भवन निर्माण का विधिवत भूमि पूजन किया गया। यहां सरकार ने अखिल गढ़वाल सभा को भवन निर्माण के लिए पांच बीघा जमीन आवंटित की है। सभा के सांस्कृतिक सचिव पंडित उदय शंकर भट्ट के नेतृत्व में आमंत्रित वरिष्ठजनों ने वैदिक मंत्रोचार के साथ भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन और भवन निर्माण शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित करते हुए अखिल गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन लाल धस्माना ने कहा कि लंबे समय से इस भूमि पर धर्मशाला एवं संग्रहालय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना काल में सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई भूमि पर चाहरदीवारी की गई थी। अब निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। इस सामुदायिक विकास भवन की निर्माण हेतु डोईवाला क्षेत्र के विधायक बृजभूषण गैरोला की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने समाज एवं सभा के से जुड़े लोगों से अपील की हुए सभा को आर्थिक सहयोग देने का कष्ट करें ताकि प्रस्तावित निर्माण कार्य की भी शुरुआत की जा सके।

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सचिवालय कूच का ऐलान

देहरादून। उत्तराखंड में दैनिक वेतन, संविदा, पीटीसी, उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होने जा रहा है। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने तीन सितंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। रैली वाले दिन ही अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया जाएगा। महासंघ की बुधवार को देहरादून गांधी रोड में हुई बैठक में आंदोलन का ऐलान किया गया। महासंघ अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि जिन भी संविदा, दैनिक वेतन, पीटीसी, उपनल कर्मचारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। उन्हें नियमित किया जाए। जल्द से जल्द नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से कोई एक बार नहीं, बल्कि कई बार कर्मचारियों को नियमित किए जाने के आदेश किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जो कर्मचारी तत्काल नियमित नहीं हो सकते, उन्हें समान काम का समान वेतन उपलब्ध कराया जाए।महासचिव बीएस रावत ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर तीन सितंबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया जाएगा। प्रदेश भर से कर्मचारी इस कूच में शामिल होंगे। रैली में सभी निगम संघ, यूनियन, संगठन, परिषद अपने अपने बैनर तले शामिल होंगी। रैली के ही दिन अगले कार्य बहिष्कार, टूल डाउन का ऐलान कर दिया जाएगा। बैठक में दिनेश पन्त, प्रेम सिंह रावत, शीशपाल रावत, टीएस बिष्ट, श्याम सिंह रावत, मेजपाल , संदीप मलहोत्रा, गौरब बर्नवाल, ओम प्रकाश भट्ट, राजेश रमोला, चतर सिंह, जीवा नन्द, दिवाकर शाही, राकेश पेटवाल आदि मौजूद रहे।

राज्यपाल ने राजभवन में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली

विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों के औचक निरीक्षण करें कुलपतिः राज्यपाल

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधाओं और उनके सर्वांगीण विकास में कोई कोर कसर न रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी केन्द्रित होनी चाहिए और छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ही हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने क्रियाकलापों में टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करते हुए ई–कल्चर लाने का प्रयास करें। राज्यपाल ने बुधवार को राजभवन में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कुलपतियों के अलावा शासन के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करने, एक–दूसरे से समन्वय हेतु एमओयू करने और उनका प्रचार–प्रसार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी कुलपतियों द्वारा ह्यह्यवन यूनिवर्सिटी–वन रिसर्चह्लह्ल पर किए जा रहे लघु शोध प्रबन्ध पर अद्यतन प्रगति के बारे में अवगत कराया। गौरतलब है कि राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालय को राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु एक वर्ष तक अपने गहन शोध के माध्यम से लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपने शोध के विषय का चयन किया गया है जिसकी रिपोर्ट जनवरी 2025 तक प्रस्तुत की जानी है।

राज्यपाल ने कहा कि यह शोध प्रबन्ध राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में लाभप्रद होगा और इस पर गंभीरता से कार्य किया जाय। उन्होंने कहा कि शोध प्रबन्ध तैयार होने के उपरांत उसका प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव एवं संबंधित विभाग के सचिव के समक्ष किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कुलपतियों को निर्देश दिए कि राजभवन को प्राप्त अस्थायी सम्बद्धता प्रस्तावों पर विसंगतियों के संबंध में विश्वविद्यालय का अभिमत नितांत जरूरी है इस पर संबंधित विश्वविद्यालय अपने स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरणों को अग्रसारित करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सम्बद्धता के उन्हीं प्रकरणों को राजभवन प्रेषित करें जो मानको में पूर्ण हों।

इस बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए तैयार किए जा रहे डैशबोर्ड के संबंध में भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि एक कॉमन डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के पास अपनी आधारभूत सुविधाओं, प्रवेश, एमओयू, बेस्ट प्रैक्टिसेज, कार्यक्रमों, विषय–विशेषज्ञों, सूचनाओं, शोध और विकास को आपस में और राजभवन के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने की सुविधा होगी। पूर्व में यह मोबाइल एप के रूप में उपलब्ध था जिसे अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ते हुए डैशबोर्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है। बैठक में कुलपतियों ने विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों और नवाचारों के बारे में अवगत कराया।

बैठक में सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, विधि परामर्शी राज्यपाल अमित कुमार सिरोही, सचिव डॉ. पंकज पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, दीपक कुमार, अपर सचिव डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, नमामी बंसल, कुलपति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय डॉ. ओ.पी.एस नेगी, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रो. एन के. जोशी, कुलपति जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति तकनीकी विश्वविद्यालय प्रो. ओंकार सिंह, कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी, कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय प्रो. दिनेश चंद्र शास्त्री, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रो. दीवान एस रावत, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, कुलपति औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय डॉ. परविंदर कौशल और कुलपति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

केदारनाथ गृर्भ गृह में सोना प्रकरण की जांच सार्वजनिक करे सरकारः नेता प्रतिपक्ष

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केदारनाथ गर्भ गृह में सोना दान किए जाने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी से कराए जाने की मांग की है। इस मामले में आर्य ने बुधवार को प्रकरण से जुड़े कई बिंदु मीडिया से साझा किए। आर्य ने केदारनाथ गर्भ गृह में सोना लगाने के संबध में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराज ने अपने बयान में कहा था कि जब दानदाता ने 23 किलो की पर्ची कटवाई तो 228 किलो सोना कैसे गायब हुआ? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अक्तूबर 2022 में मंदिर के कपाट बंद होने से पहले जब सोना लगा, तब प्रेस और मीडिया में व्यापक रुप से प्रचारित किया गया कि 228 किलो सोना लगा है। यदि 228 किलो सोना लगाने की खबर गलत थी तो मंदिर समिति या सरकार को तुरंत इसका खंडन करना चाहिए था। आर्य ने कहा कि उस समय प्रकाशित खबरों से पता चला था कि, मंदिर समिति के अध्यक्ष ने तब केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर कहा था कि इतनी अधिक मात्रा में सोना लगने के बाद केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा केन्द्रीय सुरक्षा बलों को दी जानी चाहिए। आर्य ने कहा कि इस मामले में स्वयं मंदिर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से घोटाले की आशंका व्यक्त करते हुए जांच की मांग की थी।

मामला बढ़ने पर धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने स्वयं धर्मस्व सचिव को सोना लगाने के मामले की जांच करने को निर्देशित किया था। महाराज ने 23 जून को ट्वीट कर अपने आदेश की जानकारी सार्वजनिक की थी। तब उन्होंने कहा था कि सोने के मामले में वे जल्दी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार या महाराज को मंदिर समिति की उस बैठक के कार्यवृत्त को जारी करना चाहिए, जिसमें समिति की ओर से सर्वसम्मति के साथ सोना दान लेने का निर्णय लिया गया था।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रेनकोट बांटे

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने बुधवार को भंडारी बाग स्थित मुस्लिम कॉलोनी में चाइल्ड वेल्फेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद बच्चों को रेनकोट वितरित किए।

माहरा ने इस मौके पर आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के साथ ही अपना जीवन यापन करने के लिए आज के दौर की आधुनिक शिक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस प्रकार के नाजुक हालात पैदा कर दिये हैं कि जिससे स्थितियां खराब होती जा रही हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की भरसक कोशिश हो रही है। उन्होंने अल्पसंख्यक से अपील करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों की सही शिक्षा पर ज्यादा जोर दें। उन्होंने हाल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों की घटना पर भी चिंता जताई।

शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दी बधाई

– कहा, नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलना प्रदेश के लिये गौरव की बात

देहरादून। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीणा (चमोली) की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को ह्यराष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2024ह्ल के लिये चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षिका गड़िया के प्रयास प्रशांसनीय एवं अनुकरणीय है। उनके नवाचारी प्रयासों ने छात्रों में सृजनात्मक सोच विकसित की साथ ही शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा भी मिली है। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के प्रवास पर गये प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज दूरभाष पर बात कर शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को ह्यराष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2024ह्ल के लिये चयनित होने पर ढ़ेर सारी बधाइयां व शुभकामनाएं दी। डॉ. रावत ने स्कूल को विशेष आकर्षण का केन्द्र बनाने, शिक्षा में तकनीकी नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित नवाचारी प्रोजेक्टस के माध्यम से छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने में योगदान के लिये शिक्षिका की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के उन्नयन के लिये कुसुमलता गड़िया के नवाचारी प्रयास प्रशंसनीय हैं साथ ही अन्य शिक्षकों के लिये प्रेरणादायी भी हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि कुसुमलता जैसे शिक्षक ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। सीमान्त जनपद चमोली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीणा में उनके द्वारा किये गये नवाचारी प्रयासों को राष्ट्रीय फलक पर सराहा जा रहा है जो कि प्रदेश के लिये गौरव की बात है।

क्रेच केंद्रों में मिलेंगी डे–बोर्डिंग जैसी सुविधाएं

देहरादून। प्रदेश में आने वाले समय में क्रेच केंद्रों को डे–बोर्डिंग की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। इन केंद्रों में तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसके साथ ही आबकारी विभाग की ओर से मिलने वाली एक प्रतिशत सेस की धनराशि के खर्च के लिए नियमावली तैयार की जाएगी, जिसे अनुमोदन के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक में दिशा–निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के छह माह से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार की क्रेच योजना के तहत प्रदेश में 34 आंगनबाड़ी कम क्रेच केंद्र खोले जाने की स्वीकृति मिली है। शुरूआत में प्रदेश के दो जिलों देहरादून और हरिद्वार के दो आगंनबाड़ी केंद्रों को मॉडल क्रेच केंदों के रूप में संचालित किया जाएगा। इनके सफल संचालन के बाद अन्य स्वीकृत केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा। इन केंद्रों में सभी प्रकार की मूलभूत सूविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो डे बोर्डिंग की तरह संचालित होंगे। मंत्री ने कहा कि एकल महिला योजना को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है, जिस पर वित्त विभाग की ओर से परिक्षण के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा आबकारी विभाग से मिलने वाले एक प्रतिशत सेस के रूप में अनुपूरक बजट में करीब आठ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके उपयोग को लेकर नियमावली तैयार करते हुए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में सचिव चन्द्रेश कुमार यादव, अपर सचिव प्रशांत आर्य, राज्य नोडल अधिकारी आरती बालोदी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ किया सचिवालय कूच

देहरादून। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ गांधी पार्क से सचिवालय कूच किया। सभी ने नारेबाजी कर अपना आक्रोष प्रकट किया। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले गांधी पार्क के बाहर एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए सचिवालय कूच शुरू किया। पुलिस ने बैरीकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया। कुछ देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने पार्टी के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि बढ़ रहे अपराधों को राजनैतिक और धार्मिक चश्मे से देखना बंद करना होगा, तभी अपराध रुक सकेंगे। प्रदेश संगठन सचिव सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि राज्य में हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में महिलाओं की समस्याओं से संबंधित एक विशेष सेल की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, ताकि समय रहते महिलाओं का उत्पीड़न रोका जा सके। रीजनल पार्टी की यमकेश्वर प्रभारी द्रौपदी रावत और महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष शशि रावत ने भी सरकार पर निशाना साधा। इस अवसर पर रामेश्वर पांडेय, अनुपमा भारद्वाज, मनोरमा चमोली, उपेंद्र सकलानी,अंजू रावत, पदमा रौतेला, ऋृषिका चौहान, रिकीं कुकरेती, शान्ति चौहान, मंजू रावत, रजनी कुकरेती समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com